

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, मध्यप्रदेश
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E)-II, Madhya Pradesh

Address : Lekha Bhawan, Jhansi Road, Gwalior-474002
Phone : 0751-2323968
Fax : 0751-2432194

पता : लेखा भवन, जंसी रोड, ग्वालियर -474002
दूरभाष : 0751-2323968
फैक्स : 0751-2432194



क्रमांक/पेंशन/डी.आर.एस.एस.ए./छत्तीसगढ़-03/2024-25

दिनांक:-

प्रति,

सभी जिला कोषालय अधिकारी
मध्य प्रदेश

विषय:- अन्य राज्यों के पेंशन प्राप्त कर रहे सेवा निवृत्त न्यायिक अधिकारियों (पेंशनर एवं परिवार पेंशनर) को स्वीकृत भत्तो एवं सुविधाओ (मेडिकल भत्ता एवं डोमेस्टिक हेल्प/ अर्दली भत्ता) के भुगतान के संबंध में।

- संदर्भ:- 1. कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त पत्रांक पी.ए./छत्तीसगढ़ राहत आदेश/वि.मु.प्र. पत्र/449 दिनांक 06.06.2024
2. उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के पत्र क्रमांक 3079/दो-15-2/2024 बिलासपुर दिनांक 19.02.2024.

उपरोक्त विषय में लेख है कि कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त संदर्भित पत्रांक (2) के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों (पेंशनर एवं परिवार पेंशनर) जो अन्य राज्यों से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, स्वीकृत भत्तो एवं सुविधाओ (मेडिकल भत्ता एवं डोमेस्टिक हेल्प/ अर्दली भत्ता) के भुगतान के आदेशों की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त विषयानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। उपरोक्त संदर्भित आदेशों की प्रति कार्यालय महालेखाकार मध्यप्रदेश की वेबसाइट www.agmp.nic.in पर भी उपलब्ध है।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पेंशन

क्रमांक/पेंशन/डी.आर.एस.एस.ए./छत्तीसगढ़-03/2024-25 /1147

दिनांक:- 25-6-24

प्रतिलिपि:-

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त पत्रांक पी.ए./छत्तीसगढ़ राहत आदेश/वि.मु.प्र. पत्र/449 दिनांक 06.06.2024 के संबंध में सूचनार्थ।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पेंशन



SP-336829340

क्रमांक: पी.ए./छत्तीसगढ़ राहत आदेश/वि.मु.प्रा.पत्र./ 449

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL

(ACCOUNT & ENTITLEMENT) CHHATTISGARH, RAIPUR

54525

दिनांक : 06.06.2024

Date :

प्रति,

महालेखाकार (लेखा एवं हक.) -II,
मध्य प्रदेश, लेखा भवन, झाँसी रोड,
ग्वालियर (म.प्र.)-474002

502559

विषय:- अन्य राज्यों से पेंशन प्राप्त कर रहे सेवा निवृत्त न्यायिक अधिकारियों (पेंशनर एवं परिवार पेंशनर) को स्वीकृत भत्ता एवं सुविधाओ (मेडिकल भत्ता एवं डोमेस्टिक हेल्प / अर्दली भत्ता) के भुगतान के संबंध में।

संदर्भ :- उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के पत्र क्रमांक 3079/दो-15-2/2024 बिलासपुर दिनांक 19.02.2024.

संदर्भित निर्देशों का पालन करने एवं संबन्धित सभी कोषालयों एवं बैंकों को अपने स्तर से सूचित करने हेतु प्रेषित।
कृपया इसकी पावती भेजने का कष्ट करें।

संलग्न: संदर्भित आदेश की प्रति।

भवदीय

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए.

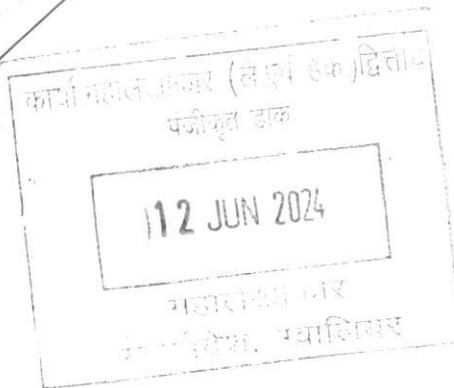
पृ.क्र. पी.ए./छत्तीसगढ़ राहत आदेश/
प्रतिलिपि:

दिनांक:

कार्यालय संभागीय सयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन रायपुर छ. ग. के पत्र क्रमांक /संसंरा/न्याया./
2024/343 दिनांक 22.05.2024 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

Sh. Anand
13/6/24

DA-SS
13-6-24



वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए.

कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन रायपुर छ.ग.

दूरभाष क्रमांक 0771-2229772 फ़ैक्स नम्बर 0771-2228329, ईमेल jd.raipur.cg@nic.in

क्रमांक / संसंसंरा / न्याया. / 2024 / 343
प्रति,

रायपुर दिनांक 22.10.24 / 2024

महालेखाकार,
कार्यालय महालेखाकार
रायपुर (छ0ग0)

विषय :- अन्य राज्यों से पेंशन प्राप्त कर रहे सेवा निवृत्त न्यायिक अधिकारियों (पेंशनर एवं परिवार पेंशनर) को स्वीकृत भत्तों एवं सुविधाओं (मेडिकल भत्ता एवं डोमेस्टिक हेल्प/अर्दली भत्ता) के भुगतान के संबंध में।

संदर्भ :- उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के पत्र क्रमांक 3079/दो-15-2/2024 बिलासपुर दिनांक 19 फरवरी 2024।

--0--

छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग रायपुर के संदर्भित आदेश की प्रति आपकी ओर संलग्न प्रेषित है। उक्त आदेशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के न्यायालयों एवं प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ न्यायिक अधिकारियों तथा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों (पेंशनर एवं परिवार पेंशन सहित) को स्वीकृत मेडिकल भत्ता एवं डोमेस्टिक हेल्प एलाउंस का देय दिनांक 01.01.2016 से भुगतान किया जाना है। उक्त भत्तों का भुगतान अन्य राज्य से पेंशन प्राप्त कर रहे सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को भी किया जाना है।

अतः आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र आपकी ओर सादर प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


पृ. क्रमांक / संसंसंरा / न्याया. / 2024 /
प्रतिलिपि :-

पेंशन संवितरण अधिकारी, जबलपुर / होशंगाबाद / कटनी / उमरिया (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

संभागीय संयुक्त संचालक
कोष लेखा एवं पेंशन रायपुर
रायपुर दिनांक / 2024संभागीय संयुक्त संचालक
कोष लेखा एवं पेंशन रायपुर

सेवा निवृत्त न्यायिक अधिकारियों की सूची

स.क्र.	जिला कोषालय का नाम	पेंशन/परिवार पेंशनर न्यायिक अधिकारी के नाम	पीपीओ नंबर
1	2	3	4
1	कटनी (म0प्र0)	श्री लाखन सिंह	08 एच. सी. / 36473
2	उमरिया (म0प्र0)	श्रीमती जगरानी देवी पत्नी स्व. श्री छोटेलाल सिंह देकाम	08 एच. सी. / 22445
3	जबलपुर (म0प्र0)	श्री वृजमोहन टंडन	08 एच. सी. / 10047
4	होशंगाबाद (म0प्र0)	श्रीमती बृजबाला पटेल, पत्नी स्व0 श्री अम्बरीश कुमार पटेल	08 एच. सी. / 15400


 संभागीय संयुक्त संचालक
 कोष लेखा एवं पेंशन रायपुर (छ0ग0)

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

//ज्ञापन//

क्र. 3079 /
दो-15-2/2024

बिलासपुर, दिनांक 19 फरवरी, 2024

प्रति,

संभागीय संयुक्त संचालक,
कोष, लेखा एवं पेंशन,
रायपुर (छ0ग0)

विषय :- राज्य के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों (पेंशनर एवं परिवार पेंशनर) को स्वीकृत भत्तों एवं सुविधाओं (मेडिकल भत्ता एवं डोमेस्टिक हेल्प/होम अर्दली भत्ता) के भुगतान के संबंध में।

संदर्भ :- छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला-रायपुर का आदेश क्रमांक 324/PS LAW/89/XXI-B/CG/24 dated 16/02/2024.

—00—

छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के संदर्भित आदेश की प्रति आपकी ओर संलग्न प्रेषित है। उक्त आदेशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के न्यायालयों एवं प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ न्यायिक अधिकारियों तथा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों (पेंशनर एवं परिवार पेंशन सहित) को स्वीकृत भत्तों एवं सुविधाओं को देय दिनांक से भुगतान किया जाना है।

अतः सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों (पेंशनर एवं परिवार पेंशनर) को पेंशन के साथ देय भत्तों यथा- मेडिकल भत्ता एवं डोमेस्टिक हेल्प एलाउंस का भुगतान देय दिनांक से कराने हेतु समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, रायपुर एवं दुर्ग सहित उन सभी प्राधिकारियों को विधि विभाग के आदेश की प्रति प्रेषित कर भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करने तथा इस रजिस्ट्री को अवगत कराने का आपसे अनुरोध है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

19/2/24
(सुधीर कुमार)
रजिस्ट्रार जनरल

Order dt.16.2.24

From : Govt. of C.G., Law Department <lawdept.cg@gov.in>
Subject : Order dt.16.2.24
To : Registrar General High Court of Chhattisgarh
<rg.cg@indiancourts.nic.in>

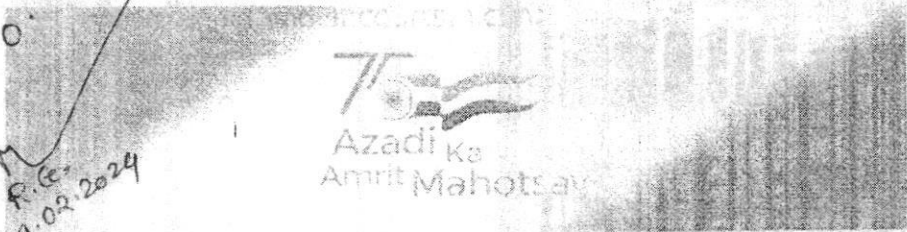
Fri, Feb 16, 2024 09:37 PM
1 attachment

PFA

Regards :

Under Secretary
Government of Chhattisgarh,
Law and Legislative Affairs Deptt.
Mahanadi Bhawan, Mantralaya
Nawa Raipur Atal Nagar, Distt. Raipur (Chhattisgarh) 492002
Phone No. 0771-2510346, Fax No. 0771-2221346
Website - <https://law.cgstate.gov.in>

B.O.
M
R.G.
19.02.2024



Under Secretary
Government of Chhattisgarh,
Law and Legislative Affairs Deptt.

Registrar General.pdf
9 MB

3

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
LAW & LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT
MAHANADI BHAWAN, NAVA RAIPUR, ATAL NAGAR,
MANTRALAYA (C.G.) 492002

Phone No. 0771-2221346 Fax No. 0771-2510346

Email-lawdept.cg@gov.in

Raipur, Dated 16/02/2024

**CHHATTISGARH LOWER AND HIGHER JUDICIAL SERVICE
ALLOWANCES ORDER, 2024**

ORDER

No. 324/PS LAW/89/XXI-B/C.G./24.- WHEREAS, The Hon'ble Supreme Court of India, New Delhi in W.P. (C) No. 643/2015 All India Judges Association vs. Union of India & Ors., vide its Order dated 09TH May, 2017 appointed Second National Judicial Pay Commission under the Chairmanship of Mr. Justice P. Venkatarama Reddi (P.V. Reddi), former Judge of Supreme Court of India for the purpose of revision of Pay and Other conditions of Service of members of the District Judiciary;

AND WHEREAS, the Hon'ble Supreme Court of India in its Judgment dated 27th July, 2022 and 19th May, 2023 has accepted the recommendation of the Second National Judicial Pay Commission on revision of pay and pension of the Judicial Officers and accordingly State Government has revised pay and framed rules in respect of revision of pay, pension and other retirement benefits of the members of the Chhattisgarh Lower and Higher Judicial Services;

AND WHEREAS, the Hon'ble Supreme Court of India in its Judgment dated 4th January, 2024 has issued directions with respect to the allowances payable to the Judicial Officers, Retired Judicial Officers and Family Pensioners as recommended by the Second National Judicial Pay Commission;

NOW THEREFORE, in supersession of this Department's Order No. 13040/XXI-B/CG/06, dated 31.10.2006 (as amended from time to time), the State Government, in due compliance with the directions delivered in said Judgment dated 4th January, 2024, is pleased to sanction following allowances payable/reimbursed to the Judicial Officers (including those who are posted in any department of the State on deputation), namely:-

1. House Building Advance (HBA), -

- (1) HBA shall be made available to Judicial Officers in terms of the House Building Advance Rules, 2017; and
- (2) HBA shall be available to Judicial Officers also for the purchase of a ready built house from private individuals subject to such safeguards as may be prescribed by the State Government in consultation with the Hon'ble High Court of Chhattisgarh.

2. **Children Education Allowance (CEA).-**

- (1) Judicial Officers shall be entitled for Children Education Allowance with effect from the academic year 2019-2020;
- (2) They shall be entitled for Rs 2,250 per month as CEA and Rs 6,750 per month as hostel subsidy for two children up to Class 12;
- (3) For children with special needs, the reimbursement would be at double the rate stated in sub-clause (2).
- (4) When the DA increases by 50%, the allowances and subsidy shall increase by 25%; and
- (5) Further, reimbursement will be done just once every year, after completion of the financial year. For reimbursement of CEA, a certificate from the head of institution, where the ward of Judicial Officer studies, will be sufficient for this purpose. The certificate should confirm that the child studied in the school during the previous academic year. For Hostel Subsidy, a similar certificate from the head of institution will suffice, with the additional requirement that the certificate should mention the amount of expenditure incurred by the Judicial Officer towards lodging and boarding in the residential complex. The amount of expenditure mentioned, or the ceiling as mentioned above, whichever is lower, shall be paid to the Judicial Officer.

3. **Concurrent Charges Allowance.-** Concurrent Charge Allowance is payable to officers, who are required to hold full charge of the duties of equal or higher responsibilities in addition to the duties of their own post.

- (1) The concurrent charge allowance to be available maximum at the rate of 10% of the minimum of the scale of the additional post held beyond a period of ten working days.
- (2) No upward revision in the percentage of the Concurrent Charge Allowance.
- (3) Hon'ble High Court to decide the Concurrent Charge allowance to be available to the Officer within the ceiling of 10% on the basis of the number of days worked, the quantum of judicial work turned out and the administrative work handled.
- (4) There shall not be any insistence on the performance of 'appreciable judicial work' of the Court concerned.

4. Conveyance/Transport Allowance (TP).-

(A) Official Vehicle,-

(1) The following Judicial Officers are eligible for official vehicles, namely,-

- (i) In the cadre of Principal District Judge;
- (ii) Director, Chhattisgarh State Judicial Academy;
- (iii) Judge, Family Court;
- (iv) Special Judge under the Schedule Castes and Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act. 1989;
- (v) First Additional District Judge;
- (vi) Chief Judicial Magistrate;
- (vii) Secretary, District Legal Services Authority.

(2) The quantum of petrol/diesel for official cars would be raised to the actual consumption for official purposes as certified by the concerned official and supported by a log book, which would be maintained. The judicial officers using official cars may be permitted to use them for private purposes to the extent of 300 kms per month;

(B) Own Vehicle,-

(1) The transport allowance at the rate of Rs 10,000 per month w.e.f 01.01.2016 be given to those Judicial Officers, who own the car so as to cover the cost of maintenance and driver's salary and this will be increased to Rs 13,500 from 01.01.2021. The transport allowance would be payable at a reduced rate of Rs 4,000 per month, where there is a existing practice of allocating a driving-

(2) The knowing office attendant/peon to the officer;

(2) In addition to the transport allowance, there should be a reimbursement of the cost of,-

FOUR WHEELER	100 litres of petrol/diesel in District Headquarters and 75 litres of petrol/diesel in other areas
--------------	--

Explanation.- Own Vehicle means vehicle registered in the name of the Judicial Officer or his/her spouse.

- (C) The Judicial Officers shall be permitted to exhibit a sticker at their option on the lower left side of the windscreen with inscription 'Judge' printed in moderately sized letters; and
- (D) Soft loan facilities to the extent of Rs 10 lakhs at nominal interest for the purchase of car shall be extended to the judicial officers. Guidelines/ Rules regarding issuance of soft loans (including provision of interest rate as applicable in GPF) as well as provisions of reimbursement, shall be issued separately.

5. Earned Leave Encashment:-

- (1) Judicial Officers, shall be entitled to a maximum limit of 300 days leave encashment at the time of retirement w.e.f 01.01.2024.
- (2) A judicial officer shall be entitled to encash :
 - (a) 10 days earned leave while availing LTC subject to maximum 60 days – 10 at a time upto six occasions during the entire service.
 - (b) 30 days in a block of two years.
 - (c) S.No.(a) and (b) shall be in addition to the right of the Judicial Officers to encash upto 300 days EL at the time of retirement.
- (3) In case of officers, who have retired and while granting leave encashment at the time of retirement, the leave encashment availed during service stand adjusted, shall be paid the amount of the so adjusted earned leave, at the time of retirement as explained in the example below:-

Example :

Leave encashed during service	120 days
Leave to the credit of the officer on the date of retirement	300 days
Maximum Leave to be encashed at the time of retirement	300 days
Eligible to get encashment of leave	300 days
Leave encashment granted at the time of retirement (120 days leave deducted on account of encashment during service)	300 - 120 = 180 days instead of 300 days
That 120 days leave encashment is required to be given to the officer now.	

- (4) Judicial Officer shall not be insisted for availing leave.

(5) For encashment of leave the block period of 2 years shall start from 01.11.2023.

6. Electricity and Water Charges.-

- (1) The 50% of the electricity charge and water charge consumed at the Residence shall be reimbursed.
- (2) The ceiling in terms of units of electricity and the quantity of water consumed shall be as follows:

Designation	Electricity Units	Water Quantity
District Judges	8000 units per annum	420 Kls per annum
Civil Judges	6000 units per annum	336 Kls per annum

- (3) Reimbursement of electricity and water charges shall be on the quarterly basis on production of proof of payment of the billed amount. The ceiling of units shall be strictly counted on yearly basis.
- (4) This allowance shall be available at the enhanced rates w.e.f. 01.01.2020.

7. Higher Qualification Allowance.-

- (1) The Judicial Officers shall be granted three advance increments for acquiring higher qualification i.e. post- graduation in law and one more advance increment, if he acquires Doctorate in Law.
- (2) The advance increments once granted for post-graduation degree or Doctorate in law shall not be again granted if, in future, the officer acquires post graduate or Doctorate degree in any other subject.
- (3) The advance increments shall be available to the officer who had acquired the post-graduation degree or Doctorate either before recruitment or at any time subsequent thereto while in service.
- (4) The advance increments shall be granted from the date of initial recruitment, if the officer has already acquired the postgraduation degree or Doctorate and from the date of acquiring the post-graduation or Doctorate degree, if acquired after joining the service.
- (5) The advance increments shall be available in the District Judge Cadre from District Judge (Entry Level) to District Judge (Selection Grade) and from District Judge (Selection Grade) to District Judge (Super Time Scale).

- (8)
- (6) The advance increments for all practical purposes shall be part of salary and Dearness Allowance shall be available on the same.

8. **Leave Travel Concession(LTC)/Home Travel Concession(HTC).-**

- (1) The Judicial Officers may be permitted to avail one LTC and one HTC in a block of 3 years.
- (2) Encashment of 10 days earned leave while availing LTC (not HTC) (subject to the maximum of 60 days) can continue. The same will be in addition to encashment of 300 days at the time of retirement and 30 days in a block of two years.
- (3) As far as fresh recruits are concerned, the HTC shall be allowed 2 times in the first block of 3 years. However, the block of 3 years will commence on completion of the period prescribed for probation (not necessarily declared)
- (4) The Judicial officers irrespective of their rank shall be allowed to travel by air and the reimbursement shall be made subject to the condition that the tickets have been purchased either directly from the Airlines or from the agents authorized, namely, Ashoka Travels, Balmer and Lawrie and IRCTC by the Central/State Government subject to further addition or deletion of the authorized agent by the Central/State Government.
- (5) The other details such as class of travel, carry over, advance, etc. shall be governed by the respective rules/orders of the State;
- (6) The Judicial officers may be allowed to carry forward LTC anywhere in India beyond retirement for a period of one year.
- (7) The Judicial officers shall not be required to avail of earned leave only, for LTC/HTC purpose and they may be permitted to avail of casual leave as a prefix and suffix to the extent of two days.
- (8) Block period of three years shall start from 01.01.2024.

9. **Medical Allowance/Medical Facilities.-**

- (1) Fixed medical allowance shall be payable @Rs.3,000/- p.m. to the serving Judicial Officers with effect from 01.01.2016;
- (2) Fixed medical allowance shall be payable @Rs.4,000/- to the pensioners and family pensioners with effect from 01.01.2016;
- (3) The spouse or other dependents of Judicial Officers drawing family pension shall also be eligible for medical facilities/reimbursement at par with the pensioners of the judiciary;

(4) Regarding Medical Treatment of Judicial Officers and their Family members and Reimbursement procedure shall be governed by this Department's Order No. 13040/XXI-B/CG/06, dated 31.10.2006 (as amended from time to time) and this Department letter (clarification) no. 5738/3123/21-B/C.G./2011, dated 26.8.2011, till further Order is issued as per the Order dated 04.01.2024 of the Hon'ble Supreme Court of India.

10. Newspaper and Magazine Allowances.-

- (1) Ceiling limit of Reimbursement for newspaper and magazines shall be Rs.1000/- p.m. for District Judges (two newspapers and two magazines) and Rs.700/- p.m. for Civil Judges (two newspapers and one magazine).
- (2) The reimbursement shall be on half yearly basis from January to June and July to December, on the basis of self certification.
- (3) The allowance at the above mentioned rates shall be available from 01.01.2020.

11. Robe Allowance.-

Judicial Officer shall be entitled for Robe allowance of Rs 12,000 once in three years with effect from 01.01.2016.

12. Special Pay for Administrative Work.-

- (1) Special Pay for Judicial officers doing administrative work shall be payable to:
 - (a) Principal District and Sessions Judges : Rs.7000/- per month
 - (b) Other District Judges including 1 Additional District Judges entrusted with administrative work who have to generally spend time beyond Court working hours : Rs. 3500/- per month.
 - (c) District Judges presiding over Special Courts and Tribunals having independent administrative responsibilities : Rs.3500/- per month.
 - (d) CJMs and Principal Senior, Junior Civil Judges and other Judicial Officers having administrative responsibilities being in charge of independent Courts with filing powers : Rs.2000/- per month.
- (2) The Special Pay shall be available w.e.f. 01.01.2019.

13. Sumptuary Allowance.-

- (1) The sumptuary allowance shall be available to the Judicial Officers at the following rates :
District Judges Rs. 7,800/- per month

Civil Judges (Sr. Div.) Rs. 5,800/- per month

Civil Judges (Jr. Div.) Rs. 3,800/- per month

(2) The allowance shall be available w.e.f. 01.01.2016.

(3) The following categories of Judicial Officers shall get Rs.1,000/- (One thousand) more by virtue of their status or the additional responsibilities they shoulder:-

- Principal District Judge in-charge of administration in the Districts/Cities.
- District Judges in selection grade and super time-scale.
- Director of Chhattisgarh State Judicial Academy/Member Secretary, State Legal Services Authority.
- Chief Judicial Magistrate.

(4) No sumptuary allowance shall be payable to retired Judicial Officers.

14. Telephone Facility.-

(1) The Judicial Officers shall be provided with the following telephone facilities.-

i. Residential Telephone (Landline) :

(a) The landline telephone and broadband facility (by the same or different service providers) shall be provided at the residence of the Judicial Officers with the permitted user as follows :

District Judges : Rs.1500/- per month

Civil Judges : Rs.1000/- per month

inclusive of rent, calls (local and STD both) and internet use.

(b) At places where broadband facility is not available, the permissible user shall be :

District Judges : Rs.1000/- per month

Civil Judges : Rs.750/- per month

inclusive of rent and calls (local and STD both).

ii Mobile Phone

(a) The provision of mobile phone (handset) with internet shall be as follows:

District Judge : Rs.30,000/-

Civil Judges (Jr. & Sr. Divisions) : Rs.20,000/-

And the permissible user shall be :

District Judges : Rs.2000/- per month

Civil Judges : Rs.1500/- per month

inclusive of internet data package

(b) At the request of the Judicial Officers, the mobile phone handset shall be replaced once in three years.

(c) The Judicial Officers shall be given option to retain the old mobile phone handset at a price to be determined as per the guidelines prescribed by the Registry of High Court.

iii Office Telephone.

Judicial Officers shall be provided telephone with STD and fiber network internet facility. In addition to free call charges, the installation charges and monthly rental charges shall be borne by the State Government

Limits of Bimontly Free Call Charges

District Judge (Principal District Judge/ Super-time Scale/ Selection Grade)	Rs. 3000 p.m.
District Judge (Entry Level)	Rs. 2000 p.m.
Senior Civil Judge	Rs. 2000 p.m.
Civil Judge	Rs. 1500 p.m.

15. Transfer Grant.-

- (1) On transfer, the composite transfer grant shall be equivalent to one month's basic pay
- (2) If the transfer is to a place at a distance of 20 kilometres or less or within the same city (if it involves actual change of residence), the transfer grant shall be 1/3 rd of the basic pay.
- (3) For the transportation of personal effects, the O.M. dated 13.07.2017 issued by the Department of Expenditure, Government of India pursuant to the recommendations of VII CPC shall be applicable.
- (4) In case of transportation by road, the admissible amount shall be Rs.50/- per km. inclusive of labour charges for loading and unloading or the actual whichever is lower. The said amount shall be raised by 25% when the DA increases by 50%.

(5) The Officers who have undergone transfer(s) after 01.01.2016 and their claims for transfer grant paid as per pre-revised pay scales, shall be paid the differential amount on the basis of revised pay w.e.f. 01.01.2016.

16. **Hill Area/Tough Location Allowance.-**

- (1) Hill Area/Tough Location Allowance @Rs.5000/- per month shall be paid to the Judicial Officers posted in hill areas/tough locations, as specified by the Hon'ble High Court.
- (2) More beneficial provision, if any, already applicable to the officials of the State shall be extended to the Judicial officers.
- (3) In case of doubt, whether a particular area can be considered to be hilly or tough location area, decision of the High Court shall be followed in relation to the Judicial officers.
- (4) This allowance shall be available w.e.f. 01.01.2016.

17. **Home Orderly/Domestic Help Allowance.-**

- (1) The Home-cum-office orderly allowance shall be available to the serving Judicial officers at the following rates:
 - (i) District Judges: minimum wages for one unskilled worker subject to minimum of Rs.10,000/- per month.
 - (ii) Civil Judges :60% of the minimum wages for one unskilled worker subject to minimum of Rs.7,500/- per month.
- (2) The allowance at the aforesaid rates shall be available to the Judicial Officers w.e.f. 01.01.2020.
- (3) The Judicial officers provided with Class-IV employee as an Attender/Peon/office subordinate for residential duties may exercise their option.-
 - he may either to continue with the present system and forego the allowance; or
 - he may opt for the allowance instead of availing the services of the official Attender/Peon.
- (4) (a) The payment of home orderly allowance should not result in discontinuance of practice, if any, of deputing the Office Peons/Attenders or other Class-IV employee during nights at the residences of,-
 - (i) Magistrates who are called upon to attend the Judicial work at times during night times:

- (ii) the Office Peon/Attender or such other Class-IV employee deputed for night duty at the residence of Judicial officer living in the areas generally considered to be disturbed or security risk areas or outsourced security guards to be deployed in such areas; and
- (iii) such personnel can also be deputed to the residence of Principal District Judge or equivalent rank officer having administrative responsibilities.

(b) The deployment of Peons/Attenders for such residential duties shall be subject to the availability of Class IV personnel and without detriment to Court related duties.

(5) (a) Domestic Help Allowance to the pensioners and family pensioners shall be available at the following rates from 01.01.2016 :

Pensioner : Rs.9,000/- per month

Family pensioners : Rs.7,500/- per month

(b) This allowance shall stand increased by 30% on completion of five years from 01.01.2016 that is, w.e.f. 01.01.2021.

(6) The allowance shall be drawn on the self certification of the Judicial Officer/Pensioner Family Pensioner.

18. **House Rent Allowance and Residential Quarters.**- The allowance under the above head has the following components.-

(a) RESIDENTIAL QUARTERS:

- (1) The Judicial Officer is to be provided government accommodation or requisitioned private accommodation within one month of taking charge of the post.
- (2) If the Judicial Officer is not provided with the government accommodation or requisitioned private accommodation within one month, then the Judicial Officer may secure private accommodation and should be paid rent in the following terms:
 - (i) If the rent of the private accommodation is within the admissible house rent allowance mentioned below [sub-clause (b)], no fixation of rent is required. But the concerned Judicial Officer has to certify the actual rent being paid.
 - (ii) If the rent of the private accommodation is more than permissible house rent allowance, the rent shall be assessed by Principal District Judge with the assistance of PWD officials.

(iii) If the difference between the permissible house rent allowance and the rent assessed is more than 15% and Principal District Judge may seek approval of High Court for payment of the said amount unless the officer is ready to pay the differential cost.

(3) The minimum plinth area for the residential accommodation shall be 2500 sq. ft. for District Judge and 2000 sq. ft. for Civil Judge. However, The High Court administration have the discretion to sanction the design with higher plinth area.

(b) HOUSE RENT ALLOWANCE:

(1) Judicial officers who are allotted official quarters for residence shall not be entitled to HRA;

(2) Judicial officers residing in their own houses, including the house of a parent or spouse, shall also be entitled for the recommended HRA with effect from 01.01.2016 after obtaining permission from the High Court to reside in their own house and judicial officers already residing in hired accommodation will be entitled to the recommended HRA with effect from 01.01.2020, subject to the actual rent paid within the said ceiling;

(3) The Office of the Principal District Judge or equivalent shall pay rent directly to the landlord; in which case, the officer is not eligible to draw HRA; and

(4) The SNJPC rates of HRA should be applicable to all Judicial Officers as per the notification dated 07.07.2017 which was issued after the VIIIth Central Pay Commission (CPC) by the Central Government:

Classification of Cities	Rates of HRA/pm as % of basic pay
X	24%
Y	16%
Z	8%

However, the minimum rates prescribed are 5400/-, 3600/- and 1800/- respectively. And the rate will be changed in accordance with the change in Dearness Allowance in the following terms:

Classification of Cities	Rates of HRA/pm as % of Basic Pay	When DA Crosses
X	27%	25%
	30%	50%
Y	18%	25%
	20%	50%

Z	9%	25%
	10%	50%

- (5) Z category is unclassified at present and the High Court of Chhattisgarh is at liberty to upgrade and add the cities in different classes;
- (6) In case Husband/wife both are Judicial Officers posted in the same station residing in their own accommodation shall not be entitled for HRA separately.

(c) FURNITURE AND AIR CONDITIONER ALLOWANCE:

- (1) Furniture grant of Rs.1.25 lakhs every five years shall be provided w.e.f. 01.10.2020 to the Judicial Officer subject to production of proof of purchase by the Judicial Officer. Household electrical appliances can also be purchased by availing of the said grant. The Officers having not less than two years of service will also be eligible for this allowance. The option to purchase the furniture being used by the officer at the depreciated rate shall be available at the time of fresh grant or retirement.
- (2) Apart from the furniture grant, one air-conditioner of **capacity of maximum 2 Ton** shall be provided at the residence of every Judicial Officer once in every five years.
- (3) All the aforementioned articles shall be purchased by the Judicial Officer himself/herself and utilization certificate along with the bill/receipt thereof shall be submitted by him/her to the Principal District Judge/Head of the Department which shall be kept with the service record of the concerned Judicial Officer and on transfer the Judicial Officer shall carry with himself/herself the said articles.
- (4) Judicial Officer who has ceased to be in service due to retirement or resignation, article purchased shall be retained by him/her subject to deposit of proportionate price of the articles for the remaining period of five years at the rate of 20% per year i.e. if at the time of retirement or resignation of Judicial Officer period of 3 years remain out of five year then the Officer has to deposit @ 20% of the total amount multiplies by 3. If at the time of retirement the period of six months or more remains it shall be considered one year for the purpose of computation. This rule shall be applicable for furniture provided earlier to the Judicial Officer.

- (5) In case of Death of any Judicial Officer before completion of five year no amount shall be recovered from his/her family members.
- (6) After completing of every five year articles purchased by the Judicial Officer being depreciated shall be given to him/her permanently, if he wants to retain the same voluntarily on deposit of 20% of value of the article otherwise said articles shall be auctioned by the Principal District Judge/Head of the Department and the auction money shall be deposited in the treasury. This rule shall also be applicable for furniture provided earlier to the Judicial Officers.

19. **City Compensatory Allowance (CCA).** City Compensatory Allowance shall be discontinued prospectively and no recovery shall be effected on the amount already paid on account of the allowances.

This sanction has been accorded by the Finance Department vide Dispatch No. 82/2024/Finance/Rules/Four, dated 16.02.2024.

**By Order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh**

(Rajnish Shrivastava)


Principal Secretary
Government of Chhattisgarh
Law & Legislative Affairs Department

Endt.No.325/PS LAW/89/XXI-B/C.G./2024 Nava Raipur, dated 16.02.2024

Copy forwarded to,-

- 1) Registrar General, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur,
- 2) Accountant General, Chhattisgarh, Raipur,
- 3) Deputy Secretary, Chief Secretary Office, Government of Chhattisgarh, Mantralaya, Nava Raipur for perusal,
- 4) Secretary, Finance Department, Government of Chhattisgarh, Mantralaya, Nava Raipur for perusal,
- 5) Private Secretary to Hon'ble Law Minister, Government of Chhattisgarh, Mantralaya, Nava Raipur for perusal,
- 6) Private Secretary to Principal Secretary, Law, Government of Chhattisgarh, Mantralaya, Nava Raipur for perusal,
- 7) District and Sessions Judge,.....
- 8) Principal Judge/ Judge Family Court.....

- 9) Treasury Officer, Chhattisgarh,.....
 - 10) Under Secretary, Establishment/Accounts Section, Law and Legislative Affairs Department,
 - 11) Web- site administrator, Law and Legislative Affairs Department, Government of Chhattisgarh, for uploading in the Official Website,
 - 12) Deputy Director, Govt. Regional Printing Press, in front of Indravati Bhawan, Nava Raipur, C.G. for publication in the forthcoming Gazettes (Extra Ordinary),
- for information and necessary action.

 16.2.24

(Shahabuddin Qureshi)
Additional Secretary
Government of Chhattisgarh
Law and Legislative Affairs Department